Fax : 0512-2332222 (S.O.)
011-23212648 (C.O.)

Ph.: 0512-2332222
Mob.: 09415726924

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ
Govt. Employees National Confederation
(AFFILIATED TO B.M.S.)

CENTRAL OFFICE : RAM NARESH BHAVAN, TILAK GALI, PAHAR GANJ, NEW DELHI - 110055

SUB OFFICE :
2-A, NAVEEN MARKET
KANPUR-208 001

पत्रांक सं : GENC/Mann_Ki_Baat/193(8/2/L) दिनांक : 24/08/2020

सेवा में,

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार,
नईदिल्ली|

Email:
1. *narendramodi1234@gmail.com,*
2. *connect@mygov.nic.in*

विषय:- "मन की बात" कार्यक्रम में साझा करने हेतु |

महोदय, अधोहस्ताक्षरकर्ता अनुरोध के साथ आपके द्वारा "मन की बात" के अंतर्गत देश के तमाम सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की भावनाओं से आपको अवगत कराना चाहता है जोकि इस आशा के साथ आपके समक्ष रख रहा हूं कि सरकारी कर्मचारी भी देश के 140 करोड़ लोगों में ही आते है |

महोदय देश के अल्प आय परिवारों के युवा जो अपनी निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा नहीं पूर्ण कर पाए और मैट्रिक के उपरांत आईटीआई जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण पूरा कर देश के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 41 आयुध निर्माणियों में ट्रेड्स-मैन के रूप में सरकारी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं | अचानक से आयुध निर्माणियों के निगमीकरण किए जाने के कारण चिंतामयी माहौल में है | जिनको नौकरी में आने के समय सरकारी कर्मचारियों के अंतर्गत भर्ती किया गया था | उन्होंने यह सोचा था कि नौकरी पाने के बाद से उनका जीवन और उनके साथ-साथ उनके परिवार का जीवन सुरक्षित रहेगा परंतु इन आयुध निर्माणियों के निगमीकरण किए जाने के कारण ये कर्मचारी जो इस देश की 140 करोड़ों लोगों में से ही हैं अपने भविष्य को लेकर भयभीत है कि सरकार के इस फैसले से उनका भविष्य सरकारी कर्मचारी के तौर पर कितने दिन रहेगा ? महोदय जहां तक विभागीय ढांचे की बात है निगमीकरण होने के बाद विभाग अपने खर्च ही वहन नहीं कर पाएगा क्योकि इस विभाग में ओवरहेड चार्ज स्वयं का ही बहुत ज्यादा है | कर्मचारी तथा सुपरवाइजरी व अधिकारी अनुपात भी असंतुलित है जो निगमीकरण होने के बाद और भी असंतुलित हो जाएगा, अंततः विभाग को बंद करना पड़ेगा | इसलिए इन आयुध निर्माणियों को सरकारी विभाग के रूप में ही रखा जाए ताकि देश की रक्षा सामग्री की निर्बाध आपूर्ति हो सके |

महोदय, इसी क्रम में देश के रेल मंत्रालय के अंतर्गत भी ऐसे ट्रेड्स-मैन कर्मचारी कार्यरत हैं जो रेलवे में भी निगमीकरण की घोषणाओं को सुनकर चिंतित है जबकि आपके द्वारा आपके अपने संसदीय क्षेत्र की रैली में यह आश्वस्त किया गया था कि रेलवे का निगमीकरण अथवा निजीकरण नहीं किया जाएगा | रेल मंत्रालय की जो भी उत्पादन इकाइयां हैं किसी भी तरह से घाटे में नहीं चल

रही है फिर उनको भी निगमीकरण व् निजीकरण की तरफ ढकेलना एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है | महोदय पहले से ही इन विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को "CCS पेंशन रूल 1972" से वंचित रखा गया है | अब सरकार द्वारा इन विभागों रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग के निगमीकरण/निजीकरण के फैसले से इन विभागों के सारे कर्मचारी चिंतित है क्योंकि जिस कारण से उन्होंने सरकारी सेवा में आने का निर्णय लिया था आज वह फैसला उनको निराश कर रहा है | इसलिए इन कर्मचारियों का साहस टूटने से बचाने के लिए आपको "मन की बात" कार्यक्रम के द्वारा आश्वस्त करना चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास बना रहे और इन विभागों को सरकारी विभागों के रूप में ही रखा जाए|

आज देश के तमाम युवा राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवारत हैं जिनकी सेवाओं के अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं उनके मन में भी अपने भविष्य को लेकर चिंता व भय व्याप्त है | क्योंकि वर्तमान सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण करने के प्रस्ताव को लेकर देश के तमाम नवनियुक्त युवाओं का अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है | महोदय आपके "मन की बात" कार्यक्रम के द्वारा देश के सरकारी क्षेत्रों में, बैंकिंग क्षेत्र में, रक्षा असैनिक क्षेत्र व् रेलवे में कार्यरत युवाओं की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए उनके आत्मविश्वास को टूटने से बचाया जाना चाहिए | क्योंकि इस कार्यक्रम के द्वारा आप देश की विभिन्न वर्गों की समस्याओं को लेकर देश के आम जनमानस से अपने "मन की बात" साझा कर रहे हैं | इसलिए ऐसे युवाओं का साहस टूटने से पहले इन युवा कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए "मन की बात" कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने चाहिए | ऐसी मैं आशा करता हूं |

महोदय, बैंकों के निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव के कारण बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत युवा कर्मचारी ही नहीं चिंतित है अपितु इन बैंकों में देश के नागरिकों ने जो पैसा संचय अथवा इन्वेस्ट किया है उनके मन में भी भ्रम का वातावरण है कि ऐसे में उनके द्वारा जमा की गई धनराशि का सरकार क्या करने वाली है | इस विषय की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि "मन की बात" कार्यक्रम के द्वारा इस विषय को भी देश के आम जनमानस से साझा करना चाहिए |

महोदय, पूरे देश में विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी इन्ही 140 करोड़ों लोगों में से ही है जो अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतायुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे | तो ऐसे लोगों की व्यथा को इस अनुरोध पत्र के साथ आपके संज्ञान में इस आशा के साथ रख रहा हूं कि निकट भविष्य में "मन की बात" कार्यक्रम में आपके द्वारा इन कर्मचारियों को चिंतामुक्त और भयमुक्त अवश्य किया जाएगा |

अतः महोदय से आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप "मन की बात" कार्यक्रम में इस विषय को भी देशवासियों के साथ साझा करेंगे |

धन्यवाद |

आपका ही

(साधू सिंह)
महासचिव
सदस्य, नेशनल कौंसिल (JCM)